

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
अपील संख्या 148 / 2004

पीठासीन अधिकारी



करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 लखमीचन्द पुत्र भूराराम जाति अहीर निवासी हीरवा तहसील बुहाना
जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

- 1 विशम्भर पुत्र भूराराम।
- 2 रामनिवास पुत्र भूराराम।
- 3 शेरसिंह पुत्र भूराराम।
- 4 महावीर पुत्र भूराराम समस्त जाति अहीर निवासी सागा हाल आबाद
हीरवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
- 5 बेतुल बानो बेवा झुरीखान।
- 6 सतार पुत्र झुरीखान।
- 7 इकबाल खान पुत्र झुरीखान।
- 8 शरिफ खान पुत्र झुरीखान।
- 9 आरीफ खान पुत्र झुरीखान समस्त जाति मुसलमान निवासीगण हीरवा
तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
- 10 जैतुन बेवा याकूब खान।
- 11 निसार खान पुत्र याकूब खान।

lano
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 इमरान खान पुत्र याकूब खान समस्त जाति मुसलमान निवासीगण
हीरवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

13 झुंझुनू सहकारी विकास बैंक लि० झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक झुंझुनू
सहकारी विकास बैंक लि० खेतड़ी जिला झुंझुनू।

14 जबार खान पुत्र झुरी खान जाति मुसलमान निवासी हीरवा तहसील
बुहाना जिला झुंझुनू।

15 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अ.धा. 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय
व डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी मुकदमा उनवानी
लखमीचन्द बनाम विशम्भर वगैरह दावा बाबत
घोषणा मु.नं. 78/2000 तारीख निर्णय
व डिक्री दिनांक 07.06.2004

उपस्थित

1. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शीशराम अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

lano
श्री प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्थान अपील अधिकारी
रीकर

-निर्णय-

दिनांक:-06.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा वाद संख्या 78/2000 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 07.06.2000 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने दावा बाबत भूमि खसरा नम्बर 341 रकबा 29 बिघा 11 बिस्वा वाके ग्राम हिरवा में से 3 बिघा 19 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 76/1 के सन्दर्भ में पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 341/2 रकबा 3 बिघा 19 बिस्वा झुरीखान की खातेदारी की थी जिसके वारिस रेस्पोंडेंट संख्या 12 से 14 है झुरीखान ने खसरा नम्बर 76/2 रकबा 2.78 हैक्टेयर लीलाराम वगैरह को विक्रय कर दी। जिससे रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 ने खरीद लिया तत्पश्चात यह भूमि कस्टोडियन हो गई दावा संख्या 59/94 अपीलांट ने प्रस्तुत किया था। जो स्वयं अपीलांट ने खारिज करवाया था ऐसी स्थिति में रेसजुड़ीकाटा का सिद्धान्त लागु नहीं होता है इस भूमि के सन्दर्भ में रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 ने एक दावा 84/94 प्रस्तुत कर 28.07.1995 को डिकी करवा लिया इसमें अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया, इस निर्णय के कारण अपीलांट का दावा संख्या 59/94 महत्वहीन हो गया था इसलिये उसे खारिज करवाया गया था विवादित भूमि अपीलांट ने पंजीकृत विक्रय पत्र से क्य की है अत अपीलांट खातेदारी की उदघोषणा का अधिकारी है। रेस्पोंडेंट ने अपने वाद में मेरे विक्रय पत्र को छिपा

लिया, इस पर मैंने यह वाद प्रस्तुत किया जिसमें मैंने प्रतिवादीगण को पक्षकार बनाया, झुरीखान के वारिसों ने मेरे विक्रय पत्र की ताईद की है। पूर्व दावा रेस्पोंडेंट के खिलाफ नहीं था रेस्पोंडेंट विक्रय इकरार नामा के आधार पर आये है जबकि अपीलांट ने पंजीकृत विक्रय पत्र पेश किया है। इकरार नामे के आधार पर कोई टाईटल नहीं मिलता है इस वाद के वादकरण प्रकृति, पक्षकार एवं अनुतोष दावा संख्या 59/94 से भिन्न है, हम रेस्पोंडेंट संख्या 1 के बाद में पक्षकार नहीं थे इसलिये अपील नहीं की। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध है तनकीवार विवेचन नहीं किया गया है। मैंने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से दावा साबित किया है। अपील स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2002 पेज 358, आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1474, ए.आई.आर. 1966 एस.सी. पेज 1332 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 341 रकबा 29 बिघा 18 बिस्वा का था अपीलांट ने इसमें से 3 बिघा 19 बिस्वा भूमि कौनसी दिशा में क्य की उतर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन-कौन है यह वाद में अंकित नहीं किया। विक्रय पत्र में विक्रीत भूमि की सीमाएं अंकित नहीं है अपीलांट झुरीखान के फुट स्टेप पर आ रहा है। जबकि मेरे दावे को स्वयं झुरीखान ने स्वीकार किया है, झुरीखान के वारिसान ने मेरे विरुद्ध जालसाझी की, कोई कार्यवाही नहीं की है। झुरीखान की स्वीकारोक्ति मेरे वाद में है। जिससे उसके वारिसान पाबंद है, स्टोपड है, दिनांक 28.02.1995 का निर्णय आज भी कायम है जो मेरे पक्ष में है इन्होंने अपने दावे में झुरीखान की मृत्यु होना बताया है जिसे मैंने इनकार किया है झुरीखान का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है। इसके विरुद्ध अपीलांट स्वयं द्वारा दावा संख्या 59/94 झुरीखान को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया गया था। यह दावा अपीलांट ने नोटप्रेस में खारिज

करवाया है। अदम हाजरी में खारिज नहीं हुआ है नये दावे की न्यायालय से अनुमति नहीं ली गई है। दावा संख्या 84/94 के निर्णय की जानकारी होने पर भी अपीलांत द्वारा इसे निरस्त कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि इनका दावा मान लिया जाता है तो दावा संख्या 84/94 में मेरे पक्ष में पारित निर्णय का क्या होगा। एक ही न्यायालय द्वारा एक ही भूमि के सन्दर्भ में दो निर्णय नहीं हो सकते हैं। मेरे वाद में मेरा कब्जा पटवारी ने मौका रिपोर्ट में माना है। मेरे वाद के समय अपीलांत के विक्रय पत्र की मुझे कोई जानकारी नहीं थी तो उन्हें पक्षकार कैसे बनाता, 1984 में फरगमेंट लागू था जो 1992 में हटा है। ऐसी स्थिति में इनकी रजिस्ट्री के आधार पर ही इनको अधिकार नहीं मिल सकते हैं क्योंकि यह धारा 42 का उल्लंघन है विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपीलांत की अपील सारहीन है अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2010(2) पेज 981, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 24 डीडीडीडी, राजस्थान टेनेन्सी (गोरमेन्ट)(अमेन्ड) नियम 1998 24डीडीडीडी, ए.आई.आर. 2009(एस.सी.)पेज 806 एवं ए.आई.आर. 2013 (एम.पी) पेज 119 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांत ने रिबटल में कथन किया कि धारा 29 संविदा पर है यह प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर लागू नहीं होते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 34,40,41,42,43 में हस्तान्तरण के तरीके बताये गये हैं। इसके अनुसार खातेदार द्वारा भूमि विक्रय करने पर खसरा नम्बर ही पर्याप्त होते हैं। वाद संख्या 84/94 में झुरीखान की स्वीकारोक्ति है उस प्रकरण में अपीलांत पक्षकार नहीं था मैं विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हूँ। 28.02.1995 का निर्णय अपीलांत पर लागू नहीं होगा। रेस्पोंडेंट विश्वम्बर के

Leone
 कू प्रबन्ध अधिकारी एवं
 वदेन राजस्वर अपील अधिकारी
 सीकर



बयानो से विक्रय पत्र प्रमाणित है झुरीखान के वारिसों ने भी इस स्वीकार किया है। रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टात यहाँ चस्था नहीं होते है।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि झुरीखान की होना निर्विवाद है इस तथ्य को दोनों पक्ष स्वीकार करते है विवादित भूमि के सन्दर्भ में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के समक्ष दावा संख्या 84/94 बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती प्रस्तुत किया गया था। जिसमें वादी का वाद प्रतिवादी झुरीखान की स्वीकारोक्ति पर स्वीकार किया गया है। इस निर्णय के विरुद्ध झुरीखान के वारिसों अथवा अपीलांट द्वारा कोई अपील प्रस्तुत कर इसे खारिज नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में यह निर्णय आदिनांक तक कायम है। अपीलांट द्वारा पूर्व में वाद संख्या 59/94 प्रस्तुत किया गया था जो अपीलांट द्वारा नोटप्रेस में खारिज करवाया गया है। इसके उपरान्त विचाराधीन वाद 78/2000 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रथम तो अपीलांट ने नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमती नहीं ली है। ऐसी स्थिति में वाद प्रारम्भिक स्तर पर खारिज योग्य है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 78/2000 विक्रय पत्र दिनांक 31.01.1986 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इस विक्रय पत्र में झुरीखान द्वारा ग्राम हीरवा की भूमि खसरा नम्बर 341/2 रकबा 14 बिघा 19 बिस्वा में से 3 बिघा 19 बिस्वा भूमि अपीलांट के पक्ष में विक्रय करने का अंकन है परन्तु इस विक्रय पत्र में कही भी विक्रित भूमि की चतुर्थ सीमाओं का अंकन नहीं है। जिससे यह साबित हो सके कि विक्रित भूमि वही है जिसकी खातेदारी की घोषणा वादी अपीलांट ने चाही है। यहा यह भी विचारणीय है कि विक्रय पत्र 31.01.1986 का है उस समय फरगमेंट का नियम लागु था ऐसी स्थिति में प्रस्तुत विक्रय पत्र फरगमेंट के उल्लघन के कारण भी मान्य नहीं हो सकता है।


 नू-प्रबन्ध अधिकारी
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 जयपुर

रेस्पोंडेंट के पक्ष में निर्णित दावा संख्या 84/94 के निर्णय दिनांक 28.02.1995 में झुरीखान की स्वयं की स्वीकाराई है जिसका कोई खण्डन अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा इस वाद के निर्णय को किसी भी स्तर पर चुनौति नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में इसी भूमि के सन्दर्भ में वादी अपीलांट प्रथक से नया वाद प्रस्तुत कर किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। यहां यह भी विचारणीय है कि वादी द्वारा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि कय करने का कथन किया है जिसका परिवर्तित रकबा 0.99 हैक्टेयर बनता है जबकि अपीलांट द्वारा वाद में 1.19 हैक्टेयर की खातेदारी चाही गई है। यह तथ्य भी परस्पर विरोधाभासी है विचाराधीन वाद में वादी अपीलांट ने प्रतिवादी संख्या 5 से 12 जो झुरीखान के वारिसान है को पक्षकार बनाकर उनसे राजीनाम प्रस्तुत करवाया है। प्रतिवादी संख्या 5 से 12 विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार ही नहीं है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा उनको पक्षकार बनाकर राजीनामा प्रस्तुत करवाना दूरभी संधी को जाहिर करता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पाया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।


 (करतार सिंह, पूनियाँ)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
 सीकर